

प्रेषक,

पी०सी० शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
राजकीय नागरिक उड्डयन विभाग,
वी०आई०पी० हैंगर, जौलीग्राण्ड एयरपोर्ट,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

परिवहन एवं नागरिक उड्डयन अनुभाग-2

देहरादून दिनांक २४ मार्च, 2008।

विषयः— जौलीग्राण्ड हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के फलस्वरूप बन्द हुये मार्गों के वैकल्पक मार्गों का निर्माण (जौलीग्राण्ड हास्पिटल की सीमा के अंतर्गत एयरपोर्ट की बाउन्ड्री के साथ-साथ 3.00 मीटर चौड़े सी०सी० मार्ग का निर्माण हेतु प्राप्त आगणन की वर्ष 2007-08 में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1643/रा०ना०उ०वि०/०३/०८ दिनांक 12 फरवरी, 2008 के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि जौलीग्राण्ड हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के फलस्वरूप बन्द हुये मार्गों के वैकल्पक मार्गों का निर्माण (जौलीग्राण्ड हास्पिटल की सीमा के अंतर्गत एयरपोर्ट की बाउन्ड्री के साथ-साथ 3.00 मीटर चौड़े सी०सी० मार्ग का निर्माण हेतु प्राप्त अधिशासी अभिन्नता, अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश, देहरादून के द्वारा गठित आगणन रु० 17.00 लाख (रु० सत्रह लाख मात्र) के सापेक्ष टी०ए०सी० द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत रु० 16.71 लाख (सेलह लाख इकहत्तर हजार मात्र) की लागत के आगणनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 में इतनी ही धनराशि के व्यय की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

1— उक्त धनराशि के आहरण की अलग से स्वीकृति प्रदान नहीं की जा रही है। बल्कि इस धनराशि का व्यय पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-117/661/स०ना०उ०/पी०ए०स०(कैम्प 2002)-06 दिनांक 16 जून 2006 द्वारा लोक निर्माण विभाग को स्वीकृत एवं उपलब्ध कराई गई धनराशि में से अबशेष धनराशि से वहन किया जायेगा अर्थात् कार्यदायी विभाग के पास धनराशि अवशेष में उपलब्ध होने के कारण इस शासनादेश के प्रभावस्वरूप कोई भी धनराशि कोषागार से आहरित नहीं की जायेगी।

2— कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदित करना आवश्यक होगा। निर्माण कार्य कराते समय नियमानुसार स्टोर पर्चेज नियमों का ध्यान रखा जाय।

3— कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होग।

4— कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितनी राशि स्वीकृति की गयी है।

5— एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।

6— कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोनिओवि० द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

7— कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से कार्य स्थल का भली-भाँति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए, तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

8— निर्माण सामग्री को उपयोग में जाने से पूर्व सामग्र का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए एवं इस संबंध में पूर्व मानको एवं स्टोर पर्चेस नियमों का पालन कड़ाई से किया जाए।

9— मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047 /xiv -291(2006) दिनांक 30-5-6 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने के काष्ट करें।

10—जी०पी०डब्लू फर्म-09 की शर्तों के अनुसार निर्माण ईकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण ईकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

11—इस सम्बन्ध में व्यय विवरण तथा आवश्यक वाउचर आदि सुरक्षित रखे जायेगे।

12—व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियम निर्देशों तथा अस्थाई आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति हो उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

13—आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है उसी मद पर व्यय किया जाय। एक मद का दूसरी मद में कदापि व्यय न किया जाय।

14—धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

15—स्वीकृति की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर उसकी भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रपत्र पर शासन को उपलब्ध कराई जायेगी। उक्त धनराशि का दिनांक 31-3-08 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा यदि दिनांक 31-3-08 तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

16—कार्य के निर्माण के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 5-4-04 का अनुपालन किया जायेगा।

17—कार्य अनुमोदित आगणन की सीमान्तरगत की करायी जाय किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणन/अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

18—कार्यदायी संस्था/ईकाई द्वारा निर्दिष्ट मदों/कार्यों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की मद को परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

19—कार्यदायी संस्था को आवंटित कार्य को निश्चित समय सीमा में पूर्ण कराया जाना होगा कार्य की गुणवत्ता में कमी, कार्यों में शिथिलता एवं समयबद्धता के लिये सम्बन्धित निर्माण ईकाई पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

2— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 के अनुदान संख्या-24 के लेखाशीर्षक 5053-नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-04-हवाई पट्टी का सुदृढीकरण एवं अन्य सम्बद्ध निर्माण कार्य-00-24-वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ४३ /xxvii (2)/2008 दिनांक १९ मार्च, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(पी०सी० शर्मा,)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 185/ix / नव्य/2008 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार उत्तरांचल ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
- 2- आयुक्त, गढ़वाल, मण्डल, पौडी।
- 3- निजी सचिव, माठ मुख्यमंत्री को माठ मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
- 4- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- जिलाधिकारी, देहरादून।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 7- अधीक्षण अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश, देहरादून।
- 8- अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश, देहरादून।
- 9- वित्त अनुभाग-2
- 10- गार्ड फाईल।
- 11- एनोआईसी० सचिवालय परिसर देहरादून।

आज्ञा से,

(पी०सी०शर्मा)
प्रमुख सचिव।